[Dr. Vasant Kumar Pandit]

decision has to be in line with the pharma-Shastri findings and should not be confused with the system of Astral calculations which has rightly or wrongly no following in general public and not backed by the astrologers, Shankaracharyas and Dharma Shastries. An early statement in Parliament on the Government's decision is very necessary on this issue.

(vii) NEED FOR REORGANISATION OF DAIRY BOARD AND CORPORATION

SHRI HARIKESH BAHADUR (Goakhpur): There have been serious disclosures over the last three years in respect of lop-sided development implementation of Dairy Development Projects. Large-scale diversion funds have been reported affecting seriously milk production in the country and leading to dependence on imports. There has also been large-scale imports of dairy equipment. Under Operation Flood-I, one State of Gujarat has been given Rs. 21/- crores against about Rs. 20/- crores for four important States of U.P., Rajasthan, Haryana and Punjab put together. Despite all this, there is a complete failure of milk production only in the State of Gujarat. Under Operation Flood-II, these disparities are being further aggravated due to failure of the Government to check these activities. This calls for thorough reorganisation of Dairy Board and Dairy Corporation. This is a very important issue. There-Government should take fore the immediate steps to improve the situation.

(viii) NEED FOB EXEMPTION IN EXCISE DUTY ON DIESEL FOR SMALL FISHING TRAWLERS OPERATING IN MAHARASHTRA, GUJARAT AND GOA

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): The fishermen from Maharashtra, Gujarat and Goa have come to Delhi to place their grievances before the Government. The Prime Minister has agreed to meet them and accept their memorandum. The fishermen

have earlier communicated their grievances to the Minister for Agriculture.

They have drawn the attention of the Government to the hardships caused to their fishing operations due to increase in the prices of diesel oil on account of excise duty. They have reminded the Government that though there was total exemption of excise duty on diesel in the case of big trawlers equipped with marine engines of more than 150 HP capacity on the basis Government notification, of Central such exemption was not available for poor fishermen owning mechanised boats of smaller horse power. fishermen have demanded that exemption on excise duty should be given to those poor fishermen as well and adequate subsidies should be given to them.

I request that the Government should make a statement on the legitimatedemands of the fishermen.

SHRI RAVINDRA VARMA (Bombay North): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I crave your indulgence to make a submission about this matter which is raised under rule 377. Government generally takes considerable time to make its response.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. You write to the Government and convey it to them.

SHRI RAVINDRA VARMA: But since this is a matter of urgent importance which affects the life, work and incomes of poor fishermen, your good officer may be used to request Government to give an early and sympathetic response.

(ix) NEED FOR ENSURING RE-

श्री बो॰ डो॰ सिंह (फूलपुर): पाध्यक्ष महोदय, मैं एतद् द्वारा माननीय कृषि मती जी का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन 'गुड़' की कीमतों की ग्रोर ग्राक्षित

करना चाहता हूं। इस वर्ग अप्रत्याशित रूप से गुड़ की कीमतें गिर रही हैं, जिससे सामान्य किसानों, विशेषकर छोटे किसानों की दशा बड़ी चिन्ताजनक हो गई है। गुड़ ऐसा उत्पादन है, जिससे छोटे किसान कुछ नकदी ग्राय कर लेते हैं लेकिन इस वर्श सारा गृड-गोबर हो रहा है। पुनरावृत्ति की अवश्यकता नहीं है कि देश की उन्नति किसानों की उन्नित से सम्बद्ध है । सम्भवतः सरकार इस ग़लत धारणा को विस्मृत नहीं कर पा रही है कि कृषि उत्पादों की ग्रच्छी कीमत मिलने से बड़े किसानों को ही लाभ होता है। छोटा किसान उत्पादन प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् उसे विकय कर देता है जब कि बड़े किसान कुछ समय तक प्रतीक्षा भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा सर्मायत तथा लाभकारी मूल्य से छोटे किसानों को लाभ मिल जाता है। उन ग्रधिकांश क्षेत्रों में, जहां चीनी मिलें नहीं हैं, किसान गन्ना उत्पादन करके गुड़ वनाते हैं। सरकार की कोई गड़ नीति न होने के कारण तथा गुड़ मूल्य की उपेक्षा के कारण किसानों की गाढ़ों कमाई की लूट हो रही है ग्रीर उनकी ग्रयनी परिस्थितियों की मजबूरी का नाजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है।

इस वर्ष गुड़ का मूल्य इस समय बहत गिर गया है तथा दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। कहीं कहीं पर एक रुपया किलोग्राम की दर से बिकने की स्थिति में त्रा गया है। यदि सरकार तत्काल इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं करती और किलानों के हिंत में मूल्यों का प्रभावित करने व ले विभिन्न कारकों में आवश्यक सुधार एवं हस्तक्षेप नहीं करती तो किलानों की स्थिति ग्रधिक दयनीय हो जायेगी। गुड़ को गन्ना अनुत्यादक तथा उपभोक्ता क्षेत्रों में ले जाने के लिए आवश्यक परि-वहन एवं रेल वेगनों की व्यवस्था, कृतिम ग्रधिक ग्रापूर्ति तथा कम मांग, बैंक ग्रग्निम ग्रादि कठिनाइयों के निराकरण का प्रयास सरकार द्वारा होना चाहिए।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से साग्रह ग्रन्रोध करूंगा कि वे गुड़-उत्पादकों की समस्यात्रों की ग्रोर तत्काल गंभीरत।पूर्वक ध्यान द ग्रीर उन्हें गुड़ का समुचित लाभ-कारी मूल्य दिलाने की दिशा में ग्रावश्यक प्रयास करें।

12.23 hrs.

RAILWAY BUDGET, 1982-83—GENE-RAL DISCUSSION-contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now take up further discussion on the Budget (Railways)-Mr. Jamilur Rahman, you can continue; but you have got to complete your speech within another four minutes. You have ready taken six minutes.

SHRI JAMILUR RAHMAN shanganj): Sir I come from a backward district.

MR DEPUTY-SPEAKER: Every one does so.

श्री जमीलुर्रहमान : मृहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, कल तिनसुखिया मेल के बारे में मैं कह रहा था। उस के हालत बड़ी रही है ग्रौर उस में कुछ सुधार ग्राना चाहिए। ग्रगर ग्राप को इतिकाक से उस गाड़ी में चलने का मौका मिले, तो ग्राप को बाथरूम में जाने में बड़ी कठिनाई होगी। उस गाड़ी में बैठने से ग्राप को पता चलेगा कि उसमें कितनी कठिनाई होती है। इसी तरह से बरौनी से जोगबनी वाली जो ट्रेन है ग्रीर चाहे वह प्रयाग वाली ट्रेन हो या दूसरी कोई ट्रेन हो, उन की हालत बहुत खराव है ग्रीर उस में ग्रगर ग्राप कुछ सुधार करेंगें; तो ग्रच्छी बात होगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Rahman, you can finish your speech within